

प्रेषक,

श्री(0) लाल

मन्त्रि, न्याय एवं विधि विभाग,

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,

माओ उच्च न्यायालय,

नैनीताल ।

न्याय अनुभाग:

देहादून: दिनांक 29 जुलाई, 2003

विषय: जनपद नैनीताल की छद्मनिर्वाह इकाई में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सिविल) के न्यायालय की स्थापना/परी का मृतन विधायक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार का ऐलान विभाग के मुख्य याचिका प्रबन्धक/वा.सं.वि. के पत्र संख्या-सौ/432/1/टीओसी० दिनांक 18 अगस्त, 2002 के रूप में आपके पत्र संख्या 5612/पू.एच.सी.-एडमिनि-भारत, दिनांक 21 नवम्बर, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के जनपद नैनीताल की छद्मनिर्वाह इकाई में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सिविल) के एक न्यायालय की स्थापना कराई जाए। उक्त न्यायालय के उपायार्थ संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार 09 अस्थायी संवर्गीय पदों की शासनानुदेश जारी होवे आता नियुक्ति की विधि, जो भी कार में हो, से 29 फरवरी, 2004 तक, बराबर कि ये बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, सूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पद के भारको का उक्त पद के संलग्न के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर निर्णय आदेशों के अनुसार अनुसूचित किये गये पदगार्य व अन्य भत्तों भी देय होंगे । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदधारकों की अर्हताये बड़ी होगी, जो वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों की हैं और इन पदों पर नियुक्ति पर्याप्ततः विधिपालन/कलानु कर्मचारियों के समावेशन द्वारा किया जायेगा ।

3- उक्त पदों के मूलन के अनुसार न्यायिक शासन में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे ।

4- उक्त न्यायालय के लिए सूचित कि जा रहे उक्त पदों एवं कार्यालय के लिए विभिन्न आवर्तक एवं अनावर्तक पदों में नियुक्ति विवरणानुसार रु० 9,76,000/- (रुपये नौ लाख छह हजार हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

विवरण	धनराशि(हजार रुपये में)
01-वेतन	4.63
02-मजदूरी	24
03-महागार्य भत्ता	2.27
04-अन्य भत्तों	62
05-कार्यालय व्यय	50
11-संलग्नक शासनों	42
12-फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
13-टेलीफोन	8
कुल योग -	9.76

(रुपये नौ लाख छह हजार मात्र)

5- स्वीकृत की जा रही धाराओं को व्यवस्थापक मजदूर मैन्युअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर परचेज रूलस, ट्रेडर एवं कोऑपरेटिव विभाग नियम एवं डिपार्टमेंट विभाग समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाएगा। जो उपकरण ड्राइव/ड्राइव ड्राइव ड्राइव की दरी पर है, उन्हें उन्ही दरी पर रखा किया जाएगा।

6- व्यवस्थापक मजदूर पर किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7- उपकरण एवं ट्राइप्लेटर मशीन आदि का उपयोग स्टोर परचेज नियमों एवं अन्य उद्देश्यपूर्ण विभागों के अनुसार किया जाएगा।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्यय के अनुमान संख्या-04 के अन्तर्गत- लेखाधीन "2014-15 प्रशासन-आयोजन-03-106-मिडिल और मेन्सन्स न्यायालय-06-रैलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय-00" में पृष्ठ-1 उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक दस्तावेजों के साथे डाला जाएगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अराणकोम संख्या-643/वित्त अनुभाग-3/2003, दिनांक 18.7.03 से प्राप्त उनकी सार्वजनिक से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: संशोधन।

भवदीय,
(श्री लाल)
सचिव।

संख्या:- 39-एक(1)/न्याय विभाग/2003-सदरिलोक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का प्रेषण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/एम.वि., पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को उनके पत्र संख्या-सी/432/1/टी.सी. दिनांक 18.4.2002 के संदर्भ में।
- 2- महालेखाकार, उत्तरांचल, अखंड मोटर मिलिटिंग, माजरा, देहरादून।
- 3- सचिव, रेलवे बोर्ड, परामा हाउस, नई दिल्ली।
- 4- डिप्टी कमिश्नर, ट्रेडिंग, वाणिज्य(सहायक), रेलवे मजिस्ट्रेट, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- पुलिस महानिदेश, उत्तरांचल, देहरादून।
- 6- पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रेलवे।
- 9- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तरांचल।
- 10- नियुक्ति/वित्त अनुभाग-3/आई युक्त।

आज्ञा से,
15/7
(श्री ध्यानी)
अपने सचिव।

शासनादेश संख्या- 38-एफ(1)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 19.07.

2003 का संलग्नक

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे)	1	10,000-325-15,200
2	रीडर	1	4500-125-7000
3	आशुलखक	1	4000-100-6000
4	फौजदारी अहलमद	1	4000-100-6000
5	प्रकीर्ण लिपिक	1	4000-100-6000
6	प्रतिलिपिक	1	3050-75-3950-80-4590
7	अदालती	1	2550-55-2660-60-3200
8	चपरासी	1	2550-55-2660-60-3200
9	स्वीपर (अंशकालिक)	1	2000 नियत वेतन (प्रतिमाह)
	योग-	9	

L. J. J.
(यू० सी० ध्यानी)
अपर सचिव ।